



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1938 (श०)

(सं० पटना 1031) पटना, शुक्रवार, 2 दिसम्बर 2016

सं० 2 / एम-७०-१४ / २०१२ ग०३०-९४४६

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प  
2 दिसम्बर 2016

श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण व्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 28.12.2011 को लगभग संध्या 5:30 बजे इनके द्वारा माननीय सांसद श्री निशिकांत दूबे के मोबाइल सं० 9873306633 पर फोन कर मिथ्या शिकायत के नाम पर पूछ-ताछ की गयी तथा स्वयं के उनके विरुद्ध केस का 1.0 बताया गया। माननीय सांसद सदस्य के साथ मोबाइल पर गलत भाषा का प्रयोग किया गया, साथ ही उन पर माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी की हत्या की योजना बनाने का बेबुनियाद भी आरोप लगाया गया जो श्री हरगवे के अनुशासनहीनता एवं संदिग्ध आचरण का द्योतक है।

II. श्री हरगवे के द्वारा माननीय सांसद से पूछ-ताछ के क्रममें Protocol का पालन नहीं किया गया। पूछ-ताछ के पूर्व शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों का प्रति-परीक्षण नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय सांसद से बिना किसी आवश्यकता के निहायत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ गये जो कि उनके गैर पेशेवराना अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

III. इनके द्वारा अपने आपको विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन पुलिस महानिदेशक महोदय की विद्यता से जोड़ते हुए दूरभाष पर माननीय सांसद से गरीब बच्चों की पढाई लिखाई के नाम पर सहयोग की मांग की गयी, जो कि इनके क्षेत्राधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री हरगवे का यह आचरण निश्चित रूप से अमर्यादित अशोभनीय एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

2. उक्त आरोप पर श्री हरगवे के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 16 (1) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापन-843 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा अपने बचाव में लिखित बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। श्री हरगवे के द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-६१३७ दिनांक 16.08.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच का निर्णय लिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत श्री रूप रंजन हरगवे के विरुद्ध लगाये गये प्रासंगिक आरोप को सही पाया। सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा आरोपों की प्रकृति को देखते हुए श्री हरगवे

को तीन वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना से सहमति की याचना की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं0-2253 दिनांक 02.11.2016 द्वारा दण्ड पर यह उल्लेख करते हुए यह असहमति जताई की दण्ड अनुपातिक नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी पदाधिकारी के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार ने श्री रूप रंजन हरगावे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री रूप रंजन हरगावे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतनवृद्धि संचायात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रूप रंजन हरगावे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना एवं अन्य संबंधित को भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दुर्गेश कुमार पाण्डेय,  
सरकार के उप-सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट (असाधारण) 1031-571+10-डी०टी०पी०।**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**